पंजाब सरकार ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से 990 आम आदमी क्लीनिक शुरू किए

छोटी आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से 990 आम आदमी क्लीनिक शुरू किए हैं, इनमें से 414 आम आदमी क्लीनिक शहरी क्षेत्रों में तथा 576 आम आदमी क्लीनिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. इन क्लीनिकों का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि छोटी आबादी तक उनके घरों के निकट स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें तथा विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जा सके.

राज्य में स्थापित/शुरू किए गए सभी आम आदमी क्लीनिक की मूल विशेषता मानकीकरण है, अर्थात मानकीकृत अवसंरचना योजना एवं उपयोग की जाने वाली सामग्री/वस्तुएं, मानकीकृत मानव संसाधन, दवाओं एवं जांचों की मानकीकृत सूची तथा रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत आईटी व्यवस्था.

मानव संसाधन

आम आदमी क्लीनिक में निम्नलिखित स्टॉफ द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं:- मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, क्लीनिक असिस्टेंट (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर - महिला), स्वीपर कम हेल्पर.

दवाएं

इन क्लीनिकों में मरीजों को कुल 107 दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं.

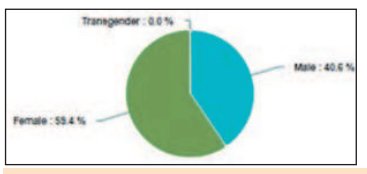

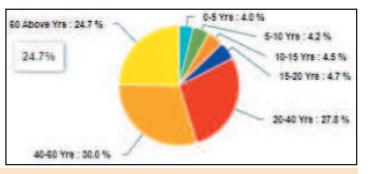

आम आदमी क्लीनिक में सेवाओं का विस्तार

अब आम आदमी क्लीनिक की सेवाओं का विस्तार कर गर्भावस्था देखभाल (सभी प्रसवपूर्व जांचें उपलब्ध), कुपोषण की जांच एवं प्रबंधन, कुत्ते के काटने का उपचार, परिवार नियोजन तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं मुख कैंसर की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन को शामिल किया गया है. प्रत्येक माह 35,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि 1,15,000 से अधिक लोगों का मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप का उपचार किया जा रहा है.

नए आम आदमी क्लीनिक प्रस्तावित

442 आम आदमी क्लीनिक प्रस्तावित हैं.

- 134 आम आदमी क्लीनिक - 78 आम आदमी क्लीनिक का कार्य पूर्ण हो चुका है और वे उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जबकि शेष 56 आम आदमी क्लीनिक का कार्य जुलाई 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा.
- 308 SHCs को AACs में उन्नत किया जाना है - कार्य प्रगति पर है, जिसके अगस्त 2026 के अंत तक पूरा होने की अपेक्षा है.

अवसंरचना योजना

प्रत्येक आम आदमी क्लीनिक में एक डॉक्टर कक्ष, एक फार्मासिस्ट कक्ष, रिसेप्शन तथा प्रतीक्षा क्षेत्र है.

जांच सुविधाएं

आम आदमी क्लीनिक में जांच सुविधाएं पीपीपी मोड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं. इन क्लीनिकों में कुल 47 प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं.

आईटी सेवाएं

ये क्लीनिक आईटी आधारित हैं, जहां प्रत्येक क्लीनिक में मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और क्लीनिक असिस्टेंट के लिए तीन टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं. मरीजों का पंजीकरण, प्रिस्क्रिप्शन तथा दवाओं का वितरण केवल इन टैबलेट्स के माध्यम से ई-सेवाएं पर किया जाता है।

क्लीनिक जिला वार

क्र.	जिला	क्लीनिक की संख्या
1.	अमृतसर	79
2.	बरनाला	17
3.	बठिंडा	48
4.	फरीदकोट	22
5.	फतेहगढ़ साहिब	23
6.	फाजिल्का	27
7.	फिरोजपुर	28
8.	गुरदासपुर	71
9.	होशियारपुर	76
10.	जालंधर	75
11.	कपूरथला	27
12.	लुधियाना	111
13.	मलेरकोटला	14
14.	मानसा	29
15.	मोगा	33
16.	पठानकोट	31
17.	पटियाला	78
18.	रूपनगर	23
19.	संगरूर	55
20.	एसएएस नगर	45
21.	एसबीएस नगर	22
22.	श्री मुक्तसर साहिब	26
23.	तरनतारन	30
	कुल	990

आम आदमी क्लीनिक में सेवा प्रदायगी

- आम आदमी क्लीनिक को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है. अब तक कुल 5.62 करोड़ से अधिक मरीजों की ओपीडी फुटफॉल दर्ज की गई है (1.81 करोड़ यूनिक मरीज / 3.81 करोड़ पुन: विजिट)
- औसतन एक आम आदमी क्लीनिक प्रतिदिन 84 मरीजों को सेवाएं प्रदान करता है, जो बड़ी संख्या में मरीजों के प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है.
- 990 आम आदमी क्लीनिक प्रतिदिन लगभग 83,000 मरीजों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं.

जनसांख्यिकी वितरण

- ओपीडी विजिट्स में 59 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है, जो लैंगिक समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है.
- बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक विभिन्न आयु वर्गों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 40-60 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है.
- सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य ओपीडी 2021-22 के 34 लाख से बढ़कर 2024-25 में 177 लाख हो गई है. यह 500 प्रतिशत की वृद्धि है.

राजमार्ग सुरक्षा

भारत की पहली समर्पित फोर्स SSF

कल्पना कीजिए कि कोई राज्य बड़े बजट सुधारों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रतीक्षा किए बिना राजमार्गों पर होने वाली मौतों को लगभग आधा कर दे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब ने ऐसा ही किया है. राज्य ने राजमार्ग सुरक्षा के लिए भारत की पहली पूर्णत: समर्पित फोर्स सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) का गठन कर सड़क सुरक्षा के स्वरूप को बदल दिया है. त्वरित प्रतिक्रिया, पेशेवर प्रशिक्षण और सेवा-प्रथम दृष्टिकोण के माध्यम से यह मॉडल देशभर में चर्चा का विषय बना है.

राज्यों के बीच तुलना से स्पष्ट होता है कि राजमार्ग सुरक्षा, तकनीक के उपयोग और जन-जवाबदेही के तरीकों में काफी भिन्नता है. इस चर्चा को तीन प्रमुख विषयों के अंतर्गत समझा जा सकता है.

नई फोर्स बनाम उन्नत पुलिस विंग- पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) इसलिए अलग है क्योंकि यह राजमार्ग सुरक्षा के लिए बनाई गई एक पूर्णत: नई और समर्पित फोर्स है इसमें 1,500 से अधिक कर्मी तैनात हैं, जिनका एकमात्र दायित्व सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पेशेवर दृष्टिकोण और उसके परिणाम- यह पेशेवर दृष्टिकोण केवल एक नारा नहीं, बल्कि बहुआयामी रणनीति पर आधारित है।

विशेषज्ञता:- नियमित पुलिस के विपरीत SSF का एकमात्र कार्य अपने निर्धारित 30 किलोमीटर के क्षेत्र में गश्त करना है. इन्हें अन्य कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों में नहीं लगाया जाता।

मृत्यु दर में कमी- इस पेशेवर और सेवा-केंद्रित दृष्टिकोण के परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं. 2024 की शुरुआत में SSF की तैनाती के बाद जिन राजमार्गों पर यह फोर्स कार्यरत है, वहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 45 से 48 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। SSF द्वारा संरक्षित सड़कों पर 2023 में 1,955 मौतें दर्ज हुई थीं, जो 2024 में घटकर 1,016 रह गईं अर्थात लगभग एक वर्ष में इन मार्गों पर करीब 940 लोगों की जान बचाई गई।

त्वरित प्रतिक्रिया :- फोर्स को 144 हाई-टेक वाहनों (जैसे टोयोटा हिलक्स और स्कॉर्पियो) से सुसज्जित किया गया है, जिससे किसी भी घटना पर 6 से 8 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह दुर्घटना के बाद जीवन बचाने वाले 'प्लैटिनम ऑवर' के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

एकमात्र लक्ष्य

एसएसएफ एक स्वतंत्र फोर्स है, इसलिए इसके कर्मियों का केवल एक ही दायित्व है :-

- सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना
- दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना
- राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन कराना
- इन्हें वीआईपी ड्यूटी, स्थानीय कानून-व्यवस्था या अन्य प्रशासनिक कार्यों में नहीं लगाया जाता.

निष्कर्ष

- सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज 45-48 प्रतिशत की कमी यह दर्शाती है कि केवल नई तकनीक पर्याप्त नहीं होती. पंजाब मॉडल यह संकेत देता है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन, सेवा- प्रथम दृष्टिकोण, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली और स्पष्ट जवाबदेही का संयोजन ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है.
- एसएसएफ की सफलता भारत के अन्य राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं, बल्कि जनसेवा और जीवन रक्षा का मिशन भी है.

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना राज्य की सबसे सफल और जनहितैषी कल्याणकारी पहलों में से एक बनकर उभरी है. इस योजना का उद्देश्य 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रद्धालुओं की धार्मिक एवं आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करना है. योजना के तहत जाति, धर्म और क्षेत्र से परे सभी पात्र श्रद्धालुओं को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है. वर्तमान में प्रतिदिन 1,100 से अधिक श्रद्धालु इस योजना के तहत विभिन्न धार्मिक एवं विरासत स्थलों की आरामदायक और सुव्यवस्थित यात्राएं कर रहे हैं. इसके लिए पंजाब भर में लगभग 95 डीलक्स वातानुकूलित बसें तैनात की गई हैं, जो श्रद्धालुओं को उनके गांव, कस्बे और शहरों से सीधे धार्मिक स्थलों तक पहुंचाती हैं. योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर सहित अनेक प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों की आस्था, सम्मान और आध्यात्मिक संतुष्टि को समर्पित पंजाब सरकार की एक अनूठी जनकल्याणकारी पहल है.

योजना का दूसरा चरण

योजना का दूसरा चरण अक्टूबर 2025 में नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित करते हुए शुरू किया गया. इस चरण के अंतर्गत श्रद्धालुओं को निम्न प्रमुख धार्मिक एवं विरासत स्थलों की यात्रा कराई जा रही है :- श्री हरमंदिर साहिब, श्री दुर्गियाना मंदिर, भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जलियांवाला बाग, पार्टिशन म्यूजियम और अन्य प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल.

नि:शुल्क सुविधाएं

संलग्न स्नानघर, स्वच्छ भोजन व्यवस्था, कीर्तन एवं ध्यान के लिए विशेष स्थान, आरामदायक एवं आध्यात्मिक वातावरण, चिकित्सा सहायता, आवश्यक किट, स्वच्छ पेयजल, आवास, अल्पाहार.

इन सभी सुविधाओं का पूरा व्यय पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रमुख उपलब्धियां

- 1,85,503 श्रद्धालुओं को लाभ
- 4,544 सफल तीर्थ यात्राएं
- प्रतिदिन 1,100 से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं
- 95 डीलक्स वातानुकूलित बसें
- 700 क्षमता वाली वातानुकूलित टेंट सिटी
- 900 स्वयंसेवकों की तैनाती

पटियाला में हाइब्रिड क्लीनिंग मॉडल लागू

30 दिन में स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य

10 जून को पंजाब सरकार ने शहरी स्वच्छता क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पटियाला में राज्य का पहला हाइब्रिड क्लीनिंग मॉडल शुरू किया. इस पहल का उद्देश्य एक माह के भीतर पटियाला को पंजाब का सबसे स्वच्छ शहर बनाना तथा आगे चलकर पंजाब को देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनाना है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब देश की सबसे उन्नत स्वच्छता प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. इस मॉडल में आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:- ऑटोमैटिक श्रब कटर मशीन, सुपर सक्शन मशीन, सड़क एवं गलियों की नियमित सफाई, प्रत्येक सोमवार विशेष सफाई अभियान.

चार-स्तरीय सफाई प्रणाली

1. जंगली घास और झाड़ियों की मशीनों से कटाई
2. बागवानी अपशिष्ट एवं बड़े कचरे का मैन्युअल संग्रहण
3. शेष कचरे की सक्शन मशीन से सफाई
4. सड़कों की धुलाई

इस प्रणाली के माध्यम से घास, मलबा और कचरे को एकीकृत प्रक्रिया में हटाया जाएगा.

सफाई कर्मियों से सीधा संवाद

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस मिशन क्लीन पंजाब की लगातार निगरानी कर रहे हैं। लुधियाना नगर निगम क्षेत्रों में औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ चाय पर चर्चा कर स्वच्छता, जलभराव और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित समस्याओं की जानकारी सीधे प्राप्त की.

उनका मानना है कि :-

जो लोग प्रतिदिन शहर को साफ रखते हैं, वही सबसे बेहतर जानते हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. यह समझ बंद कमरों में नहीं, बल्कि झाड़ू पकड़ने वाले व्यक्ति के साथ बैठकर चाय पीते हुए मिलती है.

लुधियाना के लिए विशेष लक्ष्य

पंजाब सरकार ने लुधियाना को 'ओपन मैनहोल मुक्त' और 'गड्ढा मुक्त' शहर बनाने के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की है. सभी नगर निगम अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फील्ड में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी के साथ ही 172 करोड़ के सड़क विकास कार्य किए जाएंगे. लुधियाना में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्तमान में 172 करोड़ की लागत से सड़क परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. मिशन क्लीन पंजाब का उद्देश्य केवल सफाई नहीं, बल्कि तकनीक, जवाबदेही और जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर शहरी जीवन सुनिश्चित करना है. मानसून प्रबंधन हेतु 24x7 वार रूम व्यवस्था भी की गई है. वार रूम के माध्यम से निम्नलिखित समस्याओं की रियल टाइम निगरानी की जाएगी- जिसमें जलभराव, सीवर जाम, बारिश से संबंधित शिकायतें निराकृत की जाएंगी और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा.

इन परियोजनाओं का उद्देश्य- सड़क गुणवत्ता में सुधार, नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाना है.

सरकारी नौकरियां

68228 को मिली नियुक्ति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. सरकार के गठन के बाद से अब तक विभिन्न विभागों में कुल 68228 नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को पंजाब में एक नए भर्ती संस्कृति के प्रमाण के रूप में बताया, जहां पहली बार सरकारी नौकरियां पूरी तरह मेरिट, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतियोगिता के आधार पर दी जा रही हैं, जिसमें किसी प्रकार की सिफारिश, राजनीतिक प्रभाव या भ्रष्टाचार की भूमिका नहीं है. पंजाब सरकार की यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राज्य में प्रतिभा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में एक मजबूत और कुशल कार्यबल तैयार होगा.

मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि चयन का आधार केवल कड़ी मेहनत, समर्पण और मेरिट रहा है. उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरियां सिफारिश या भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रणाली से दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि चयनित युवा अब सरकार का हिस्सा बनकर 'रंगला पंजाब' के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

प्रमुख उपलब्धियां और दृष्टिकोण

- पूरी भर्ती प्रक्रिया मेरिट और पारदर्शिता आधारित
- युवाओं के लिए रोजगार एवं अवसरों का विस्तार
- वापसी प्रवासन की शुरुआत के संकेत
- 65,000 अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम
- 25 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण
- 13 मौजूदा आईटीआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष फोकस
- उद्योग आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा
- 20 करोड़ से सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का आधुनिकीकरण
- नंगल में 23 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
- 91 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू
- छात्रों को उद्योग आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण
- नीट, जेईई, क्लेट, निफ्ट सहित परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग

1100 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न की खरीद

किसानों के खातों में सीधे 2 लाख करोड़ से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य जमा

पंजाब ने भारत के अन्न भंडार के रूप में अपनी स्थिति को पुन: मजबूत करते हुए पिछले चार खरीद सीजनों (2022-23 से 2025-26) के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 1100 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं और धान की खरीद सुनिश्चित की है. इस अवधि में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित की गई है. 2022-23 से 2025-26 तक रबी और खरीफ सीजनों में लगातार जारी इस खरीद अभियान ने राज्य की मजबूत मंडी व्यवस्था, भारतीय खाद्य निगम के साथ बेहतर समन्वय और किसानों की आय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया है. खरीद अभियान की शुरुआत रबी 2022-23 से हुई, जब पंजाब की मंडियों में 102.61 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई, जिसमें से 96.44 लाख मीट्रिक टन की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई. इस सीज़न में न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान 19,424.32 करोड़ रहा.

चार वर्षों में पंजाब में कुल 94 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक अनाज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की गई, जिससे किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिली. इस अवधि में कुल 2,37,244.66 करोड़ सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए.

विद्युत क्षेत्र में पंजाब संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरा

पंजाब का विद्युत क्षेत्र मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरा है, जहां पहले घाटे में चल रहा विभाग अब मुनाफा दर्ज कर रहा है, वह भी 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली के माध्यम से अधिकांश परिवारों के बिजली बिल शून्य सुनिश्चित किए हैं, साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने की पूर्व प्रवृत्ति को बदलते हुए 540 मेगावॉट गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट का अधिग्रहण किया और उसकी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है.

घाटे में चल रहा विभाग अब मुनाफा दर्ज कर रहा है

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई

टैरिफ दरों में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित सभी श्रेणियों में कमी की गई है, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सब-स्टेशन तथा ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है. अब तक 9,593 युवाओं को बिजली क्षेत्र में नौकरी दी गई है, जबकि 1,750 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. पंजाब पावर विभाग को A+ रेटिंग प्राप्त हुई है और यह राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो सरकार के बिजली क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और जनता को मुफ्त एवं 24x7 बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को दर्शाता है.

पंजाब सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है. पहली बार लोगों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान 8 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली है, जिसमें 95 प्रतिशत आपूर्ति दिन के समय सुनिश्चित की गई.

advertorial